

कर्म करते रहो, आज बाधा बनके जो खड़े हैं। कल तुझे ये सलामी करेंगे।

- अज्ञात



मानसून सत्र की अधिसूचना जारी

यों में बुलाया जा रहा है और सभी सांसदों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यावश्यक कार्य निपटाकर जल्द से जल्द इसे संपन्न करने की भावना ही फिलहाल सर्वोपरि है। इसलिए इस बार संसद के टाइमटेबल में कुछ बदलाव किए गए हैं।

आरती जोशी।

कोरोना महामारी के बीच 14 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी होने के साथ ही एक विवाद शुरू हो गया। यह संक्षिप्त सत्र संकटकालीन परिस्थितियों में बुलाया जा रहा है और सभी सांसदों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यावश्यक कार्य निपटाकर जल्द से जल्द इसे संपन्न करने की भावना ही फिलहाल सर्वोपरि है। इसलिए इस बार संसद के टाइमटेबल में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसमें प्रश्नकाल को समाप्त करने का प्रस्ताव भी शामिल है। इसके खिलाफ कई विपक्षी नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक है।

सरकार की तरफ से कहा गया कि लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों द्वारा बुधवार को अधिसूचना जारी किए जाने से

पहले सभी छोटे-बड़े दलों के नेताओं से राय-मशविरा कर लिया था और तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन को छोड़कर सबसे इस पर सहमति जताई थी। बहरहाल, जब अधिसूचना जारी हुई तो विपक्षी सांसदों ने इस पर तीव्र आपत्ति की। यों भी संसद का प्रश्नकाल हरेक सांसद को सरकार के क्रिया-कलापों पर सवाल करने का ऐसा अधिकार देता है, जिसे कोई छोड़ना नहीं चाहेगा।

प्रश्नकाल को संसदीय व्यवस्था की आत्मा कहा जा सकता है। संसद में ज्यादातर समय पार्टी लाइन पर बहस चलती है, लेकिन प्रश्नकाल में दृश्य अलग होता है। इस दौरान सांसद अपने तारकित प्रश्नों में सरकारी तंत्र के कामकाज से जुड़े सवाल पूछते हैं, और सरकारी जवाब से संतुष्ट न होने पर दो पूरक प्रश्नों के

जरिये सरकार को स्पष्ट जवाब देने के लिए मजबूर करते हैं।

इस दौरान अक्सर पार्टी लाइन भी धुंधली होती नजर आती है। जब-तब अपने पक्ष के ही सांसदों के सवालों से घिर जाने पर सरकार की बड़ी किरकिरी होती है। सरकार से सवाल करने और उसकी जिम्मेदारी तय करने की यह परंपरा संसदीय लोकतंत्र के उस दौर की नुमाइंदगी करती है, जब सांसद किसी पार्टी के टिकट पर नहीं बल्कि अपने दम पर चुनकर आते थे और संसद में पहुंच जाने के बाद अपना पक्ष तय करते थे। लोकतंत्र की लंबी यात्रा के दौरान राजनीतिक पार्टियां उभरीं और मजबूत होती गईं।

उन्होंने लोकतांत्रिक चेतना और प्रक्रियाओं को कितना फायदा पहुंचाया है

और किन-किन पहलुओं पर उसे कमजोर किया है, इस पर शोध होते रहते हैं, लेकिन आज की तारीख में हमारे लिए निर्दलीय लोकतंत्र की कल्पना करना भी कठिन है।

बहरहाल, प्रश्नकाल के रूप में पार्टी से ऊपर उठकर सरकार के कार्यों की पड़ताल करने के जो मौके अभी उपलब्ध हैं, उन्हें कम करने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। यह अच्छी बात है कि विपक्ष का रुख देखकर सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को मानसून सत्र में रोज आधे घंटे का प्रश्नकाल रखने और इसमें गैर-तारकित यानी लिखित जवाबों वाले सवाल लेने का सुझाव दिया है। यह पर्याप्त नहीं, फिर भी इससे मानसून सत्र एक गहरा दाग झेलने से बच जाएगा।

तैराकी या खेल

अशोक वोहरा। तैराकी या खेल, यदि आप तैरना नहीं जानते हैं तो तैराना सीख जाएं। तैराना बहुत ही खुशी देता है। यह आपके शरीर को स्वस्थ भी रखता

धर्म-दर्शन



है। इसके अलावा आप किसी गेम को अपने रोजमर्रा या साप्ताहिक जीवन का हिस्सा बना लें। जैसे बैडमिंटन खेलना, शतरंज खेलना, ताश खेलना या क्रिकेट खेलना। आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार का मनोरंजक खेल होना चाहिए। खेल से खुशियां बटोरी जा सकती है। खेल में हार-जीत के बारे में बिल्कुल मत सोचे अन्यथा खेल ही आपके दुख का कारण बन जाएगा। बस खेल को इंजाय करें। अक्सर लोग रविवार की छुट्टी के दिन सोते रहते हैं और पुरा दिन बर्बाद कर लेते हैं।

संपादकीय

नई शिक्षा नीति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आत्मा, प्राचीन भारतीय ज्ञान परम्परा को प्रतिबिंबित करती है। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन नहीं, बल्कि पूर्ण आत्म-ज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्राचीन भारत के विश्व स्तरीय संस्थानों ने अध्ययन के विविध क्षेत्रों में शिक्षण और शोध के ऊंचे प्रतिमान स्थापित किए थे, जहां विश्व के अन्य देशों के छात्र अध्ययन करने आते थे। यह वह कालखंड था, जब भारत का बौद्धिक सूर्य पूरी दुनिया को अपने ज्ञान से आलोकित कर रहा था। उस समय भारत की साक्षरता की दर 97 प्रतिशत थी।

नई शिक्षा नीति का उद्देश्य फिर से उसी सूर्य को उदित कर विश्वगुरु के तौर पर भारत को स्थापित करना है। इस नीति का लक्ष्य भारत की परम्परा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति में रचनात्मक क्षमताओं को विकसित करना है। यह नीति साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ-साथ 'उच्चतर स्तर' की तार्किक समस्या का समाधान करेगी। इससे भारत के लोगों में नैतिकता और संवेदनशीलता विकसित होगी, साथ ही यहां के युवा रोजगार के लिए सक्षम भी बनेंगे। सही मायने में कहा जाए तो यह शिक्षा नीति भारत की आने वाली पीढ़ी के लिए शुद्ध वायु की तरह है, जो उनके शरीर, मन और मस्तिष्क को मजबूत करने के साथ ही उनको उद्यमशील बनाएगी।

मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते संपूर्ण विपक्ष को उससे नेतृत्व की उम्मीद रहती है, लेकिन मुख्य पार्टी खुद नेतृत्व के संकट से जूझ रही है। बीजेपी तो पहले से ही कांग्रेसी कुनबे में आई फूट का मजा ले रही है।

भाषा के जरिए शोषण की बू

शांतनु त्रिपाठी।।

'अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए।' भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जब कोई अंग्रेजी भाषा में बात करता है, तो हमें यह वाक्य अक्सर सुनने को मिल जाता है। यह चंद शब्दों से मिलकर बना एक 'संयुक्त वाक्य' भर नहीं है। इसको सुनने और पढ़ने पर एक कटाक्ष का बोध होता, जो देश में व्याप्त अंग्रेजी और देसी संस्कृति की एक गहरी खाई को प्रदर्शित करता है। जिसमें से भाषा के जरिए शोषण की बू आती है। इस खाई को तैयार करने के लिए वर्ष 1835 में ब्रिटिश राजनीतिज्ञ लॉर्ड टॉमस बैबिंग्टन मैकाले ने शिक्षा पद्धति के रूप में पहला फावड़ा चलाया था। वह दिन-ब-दिन इतनी गहरी होती गई कि देश वैचारिक तौर पर दो भागों, भारत और इंडिया में बंट गया।

मैकाले ने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत भारत को बांटने और भाषायी एवं सांस्कृतिक गुलाम बनाने के लिए ब्रिटिश शिक्षा पद्धति को लागू किया था। जिसके विषय में उसने खुद कहा था कि 'जो शिक्षा पद्धति में लागू कर रहा हूँ उसके पाठ्यक्रम के अनुसार यहां के शिक्षित युवक देखने में हिंदुस्तानी लगेंगे किंतु उनका मस्तिष्क अंग्रेजियत से भरा होगा।' वर्तमान भारत को जब हम देखते हैं, तो मैकाले का यह कथन काफी



हद तक सत्य भी लगता है, जहां आज के युवाओं के बीच अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी संस्कृति का पिच्छलगू बनना और अपनी संस्कृति का मजाक बनाना प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया है। इस मानसिकता को समाप्त करने के लिए आवश्यक था कि हम अपनी शिक्षा नीति बनाएं और पूरे देश में उसे लागू करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से देश की तमाम ऐतिहासिक समस्याओं का समाधान निकाला गया, उसी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लिपीबद्ध कर देश ने इस समस्या का हल भी खोज लिया है। चार वर्ष में तैयार हुई नई शिक्षा नीति को एक सदी से ज्यादा का लंबा सफर तय करना पड़ा है। यह नीति भारत के लोगों को बनावटी व्यक्तित्व

और अंग्रेजी सोच एवं विचार से आजादी दिलाए वाली है। यह पूरी तरह से भारतीय मूल्यों पर आधारित है, जिसमें प्राचीन भारतीय परम्परा के सर्वोच्च लक्ष्य ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज मौजूद है।

नई शिक्षा नीति में उन सभी पहलुओं का ध्यान रखा गया है, जो इसे सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी बनाती है। इसमें एक तरफ जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव देखने को मिलता है, वहीं दूसरी तरफ भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति की झलक भी दिखती है। अपनी पुस्तक 'हिंद स्वराज' में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी लिखते हैं 'करोड़ों लोगों को अंग्रेजी शिक्षा देना उन्हें गुलामी में डालने जैसा है। मैकाले ने शिक्षा की जो बुनियाद डाली है, वह सचमुच गुलामी की बुनियाद थी। उसने इसी इरादे से अपनी योजना बनाई थी, ऐसा मैं नहीं सुझाना चाहता। लेकिन उसके काम का नतीजा यही निकला है। यह कितने दुख की बात है कि हम स्वराज की बात भी पराई भाषा में करते हैं?' इस विषय को आगे बढ़ाते हुए वह एक जगह लिखते हैं 'हमारे अच्छे से अच्छे विचार प्रकट करने का जरिया है अंग्रेजी हमारी कांग्रेस का कारोबार भी अंग्रेजी में चलता है। अगर ऐसा लंबे समय तक चला, तो मेरा मानना है कि आने वाली पीढ़ी हमारा तिरस्कार करेगी और उसका शाप हमारी आत्मा को लगेगा।'

सूडोकू नवताल-5466				☆☆☆☆ सहल			
3		8					9
	8	6		9	5		
6	5		4		7	1	
	4					2	
1	2		6			9	8
		6	4		5	8	
9				1			7

अपना ब्लॉग

गांधी जी का यह विचार सच

मोहन। गांधी जी का यह विचार सच साबित हुआ है। मैकाले द्वारा डाली गई भाषायी और वैचारिक गुलामी की बुनियाद, अब बबूल के पेड़ का रूप ले चुकी है। जिसके कांटे हम भारतीयों को वर्षों से चुभ रहे हैं। नई शिक्षा नीति का लागू होना मैकाले के इस पेड़ की जड़ में मद्दा डालने का काम करेगा। यह नीति हमें भारतीय मूल्यों से विकसित एवं गुणवत्ता-परक शिक्षा उपलब्ध कराकर भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। यह नीति हमारे छात्रों के भीतर बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्व की जागरूकता उत्पन्न करने के साथ ही भारतीय होने का गर्व भी कराएगी। इसी पुस्तक में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में गांधी जी कहते हैं 'हमें अपनी सभी भाषाओं को शानदार और उज्ज्वल बनाना चाहिए। हमें अपनी भाषा में ही शिक्षा लेनी चाहिए।'

